Online at: https://researchtrendsjournal.com ISSN No: 2584-282X

INTERNATIONAL JOURNAL OF TRENDS IN EMERGING RESEARCH AND DEVELOPMENT

Volume 2; Issue 4; 2024; Page No. 66-70

Received: 01-05-2024
Accepted: 06-06-2024

भारत में पीएमजेडीवाई के शुभारंभ से पहले और बाद में वित्तीय समावेशन की स्थिति का विश्लेषण करना

[1]Deepali Agrawal and [2]Dr. Mahadev Pandagre

[1]Research Scholar, Madhyanchal Professional University, Bhopal, Madhya Pradesh, India
[2]Department of Commerce, Madhyanchal Professional University, Bhopal, Madhya Pradesh, India

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.14271870

Corresponding Author: Deepali Agrawal

सारांश

सरकार ने वित्तीय समावेशन को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया है क्योंकि यह समावेशी विकास का एक प्रमुख प्रवर्तक है। प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों में से एक है। वित्तीय बहिष्कार गरीबी का मूल कारण है, जो स्वतंत्रता के बाद से भारत की विकास प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करता है। वे अपने सामने आने वाली वित्तीय चुनौतियों का सामना करने की अपनी क्षमता खो देते हैं। इसलिए वित्तीय समावेशन गरीबी और असमानता को कम करने का महत्वपूर्ण प्रारंभिक बिंदु है। वित्तीय समावेशन उन लोगों के आर्थिक विकास की एक व्यापक अवधारणा है जो अन्यथा देश के वित्तीय क्षेत्र से बाहर हैं। भारत ने अपनी स्वतंत्रता के बाद वर्षों तक इस मुद्दे का सामना किया है और हमेशा इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम किया है। वर्तमान अध्ययन का उद्देश्य बेंगलुरु ग्रामीण जिले में ग्रामीण गरीबों पर प्रधान मंत्री जन धन योजना के प्रभाव को कवर करना और पीएमजेडीवाई योजना की मुख्य विशेषताओं और महत्व का अध्ययन करना है।

मूलशब्द: भारत, पीएमजेडीवाई, वित्तीय समावेशन, सरकार और योजना

प्रस्तावना

ग्रामीण क्षेत्रों की बड़ी आबादी अभी भी व्यापक विकास के दायरे में नहीं आ पाई है। इस परिदृश्य पर काबू पाने के लिए वित्तीय समावेशन देश के उन्नत और उच्च आर्थिक और सामाजिक विकास की अनुमति देता है। यह समाज के वंचित और गरीब वर्गों को अधिक वित्तीय विकल्पों की आवश्यकता के लिए एक आत्मनिर्भर और पर्याप्त रूप से सूचित समाज बनाने के उद्देश्य से अधिकृत करने में मदद करता है। वित्तीय समावेशन समाज के कमजोर हिस्से और कम वित्तीय लाभ वाले समूहों जैसे कमजोर समूहों की भागीदारी को ध्यान में रखता है, जो बचत और भुगतान खाते, ऋण, बीमा, पेंशन आदि जैसी वित्तीय सेवाओं तक उनकी पहुंच के स्तर पर आधारित हैं। साथ ही मौद्रिक समावेशन अभ्यास का लक्ष्य व्यावसायिक अवसरों और शिक्षा में अधिक पूंजी की सुविधा के लिए आर्थिक सेवाओं की सरल पहुंच है। लेकिन सेवानिवृत्ति, जोखिम के खिलाफ बीमा, कृषक समुदाय और कंपनियां। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति के साथ, विशेष रूप से जब मुख्य लक्ष्य संपत्ति विकास की कार्रवाई पर है, तो सभ्यता के विभिन्न क्षेत्रों से अधिकतम भागीदारी को शामिल करने के लिए अधिक प्रयास किए जाने चाहिए। हालांकि, देश की कृषि आबादी के बीच जागरूकता और धन प्राप्ति की कमी अर्थव्यवस्था के विस्तार में बाधक है क्योंकि अधिकांश आबादी के पास औपचारिक ऋण तक पहुंच नहीं है। यह अक्सर देश के आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। ऐसी बाधाओं को दूर करने के लिए, बैंकिंग क्षेत्र कुछ तकनीकी नवाचारों के साथ उभरा जैसे कि स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम), और डेबिट कार्ड, वेब बैंकिंग, आदि।

वित्तीय समावेशन, मुख्यधारा के संस्थागत खिलाड़ियों द्वारा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से उचित वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है, जिसकी आवश्यकता कमज़ोर वर्गों और निम्न आय समूहों जैसे कमज़ोर समूहों को उचित लागत पर होती है। समावेशी वृद्धि और विकास के संदर्भ में वित्तीय समावेशन सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक बन गया है।

समावेशी वित्तीय प्रणाली के महत्व को नीतिगत हलकों में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है और यह कई देशों में नीतिगत प्राथमिकता बन गई है। दुनिया भर के कई देश अब वित्तीय समावेशन को अधिक व्यापक विकास के साधन के रूप में देखते हैं, जिसमें देश

का प्रत्येक नागरिक अपनी आय को वित्तीय संसाधन के रूप में उपयोग करने में सक्षम होता है जिसे भविष्य की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने और राष्ट्र की प्रगति में योगदान देने के लिए काम में लगाया जा सकता है।

वित्तीय समावेशन के लिए पहल वित्तीय विनियामकों, सरकारों और बैंकिंग उद्योग की ओर से की गई है। बैंकिंग क्षेत्र ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभाई है। कुछ देशों में विधायी उपाय शुरू किए गए हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिका में, सामुदायिक पुनर्निवेश अधिनियम (1997) के तहत बैंकों को अपने पूरे परिचालन क्षेत्र में ऋण देने की आवश्यकता होती है और उन्हें केवल अमीर इलाकों को लक्षित करने से प्रतिबंधित किया जाता है। फ्रांस में, बहिष्कार पर कानून (1998) एक व्यक्ति के बैंक खाता रखने के अधिकार पर जोर देता है।

जर्मन बैंकर्स एसोसिएशन ने 1996 में एक स्वैच्छिक कोड पेश किया था, जिसमें तथाकथित 'एवरीमैन' चालू बैंकिंग खाते की व्यवस्था की गई थी, जो बुनियादी बैंकिंग लेनदेन की सुविधा प्रदान करता है। दक्षिण अफ्रीका में, 2004 में दक्षिण अफ्रीकी बैंकिंग एसोसिएशन द्वारा वित्तीय रूप से वंचित लोगों के लिए मज़ांसी नामक एक कम लागत वाला बैंक खाता शुरू किया गया था। यू.के. में, प्रक्रिया के विकास की निगरानी के लिए सरकार द्वारा 2005 में एक वित्तीय समावेशन टास्क फोर्स का गठन किया गया था।

कई अफ्रीकी देशों ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल बैंकिंग के अनूठे पहलुओं का लाभ उठाया है। जी-20 (बीस लोगों का समूह) वित्तीय समावेशन विशेषज्ञ समूह की शुरुआत की गई है। अभिनव वित्तीय समावेशन के सिद्धांत नीति और विनियामक दृष्टिकोणों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं, जिसका उद्देश्य अभिनव, पर्याप्त, कम लागत वाले वित्तीय वितरण मॉडल को सुरक्षित और सही तरीके से अपनाना है, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के लिए परिस्थितियाँ प्रदान करने में मदद करना और शामिल विभिन्न बैंकिंग, बीमा और गैर-बैंकिंग संस्थाओं के लिए प्रोत्साहनों का ढांचा तैयार करना और सस्ती और गुणवत्तापूर्ण वित्तीय सेवाओं की पूरी श्रृंखला प्रदान करना है।

साहित्य की समीक्षा

चरण सिंह एट अल. (2014) भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार ने 2005 से कई उपाय शुरू किए लेकिन कई उपायों से असंतोषजनक परिणाम सामने आए। मोबाइल बैंकिंग, बैंकिंग तकनीक, भारतीय डाकघर, उचित मूल्य की दुकानें और व्यवसाय संवाददाता कुशल और उपयोगकर्ता के अनुकूल तरीके से वित्तीय समावेशन सुविधाएँ प्रदान करने के लिए प्रमुख संसाधन हैं।

गर्ग, अग्रवाल (2014) ने सरकार और आरबीआई द्वारा की गई पहलों को विभिन्न दृष्टिकोणों में वर्गीकृत किया है जिसमें वित्तीय समावेशन के लिए उत्पाद आधारित दृष्टिकोण शामिल है जिसमें नो-फिल खाते, किसान क्रेडिट कार्ड, सामान्य प्रयोजन क्रेडिट कार्ड, ओवरड्राफ्ट सुविधा के साथ बचत खाता शामिल है; बैंक लीड दृष्टिकोण में एसएचजी और बिजनेस संवाददाता शामिल हैं; नियामक दृष्टिकोण में केवाईसी, बैंक शाखा प्राधिकरण शामिल हैं; प्रौद्योगिकी आधारित दृष्टिकोण में मोबाइल बैंकिंग, शाखा रहित बैंकिंग, कियोस्क, आधार सक्षम भुगतान सेवाएं शामिल हैं और ज्ञान आधारित दृष्टिकोण में वित्तीय स्थिरता विकास परिषद और वित्तीय साक्षरता केंद्र शामिल हैं।

जॉन डी. विलासेनोर, एट अल. (2015) द्वारा ब्रुकिंग रिपोर्ट ने वित्तीय समावेशन सेवाओं और दुनिया भर में उनकी पहुंच के मामले में विकासशील देशों का तुलनात्मक अध्ययन किया। परिणामों से पता चला कि केन्या, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, रवांडा/युगांडा, चिली, कोलंबिया और तुर्की वित्तीय समावेशन के मामले में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले देश हैं। उन्होंने यह भी विश्लेषण किया कि डिजिटल वित्तीय सेवाएँ आने वाले वर्षों में वित्तीय समावेशन को गति देंगी।

वैश्विक वित्तीय विकास रिपोर्ट (GFDR, 2014) के अनुसार, वित्तीय सेवाओं का उपयोग करने वाले व्यक्तियों और फर्मों का अनुपात दुनिया भर में व्यापक रूप से भिन्न है, रिपोर्ट ने सुझाव दिया कि 2.5 बिलियन से अधिक वयस्क या दुनिया की आधी वयस्क आबादी के पास बैंक खातों तक पहुँच नहीं है। इसके पीछे मुख्य कारण खातों की कोई मांग नहीं होना और लागत, यात्रा की दूरी और कागजी कार्रवाई की बढ़ती मात्रा जैसी अन्य बाधाएँ हैं। इस प्रकार साहित्य से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि विकसित और विकासशील देश वित्तीय समावेशन की दिशा में कदम उठा रहे हैं, हालाँकि विकासशील देशों में अभी भी वित्तीय रूप से बहिष्कृत लोगों की संख्या आनुपातिक रूप से अधिक है। इस बाधा को दूर करने से गरीबी को कम करने, बचत पैदा करने, ऋण के प्रवाह में सुधार करने में मदद मिलेगी और इस प्रकार अर्थव्यवस्थाओं के विकास और वृद्धि में योगदान मिलेगा।

कुंथिया आर (2014) - इस शोध पत्र में लेखक ने हाल ही में शुरू की गई "प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई)" के विशेष संदर्भ में भारत में वित्तीय समावेशन पर हाल के घटनाक्रमों का अध्ययन करने का प्रयास किया है। लेखक ने इसके विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों, प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं का विश्लेषण प्रस्तुत किया है और देश की वंचित आबादी और बड़े पैमाने पर बैंक रहित क्षेत्रों के लिए पीएमजेडीवाई के सार्वभौमिक कवरेज को प्राप्त करने के लिए रणनीतियां सुझाई हैं।

अनुसंधान क्रियाविधि

भारत में, वित्तीय समावेशन पहली बार वर्ष 2005 में केंद्र शासित प्रदेश (UT) पांडिचेरी में इंडियन बैंक के अध्यक्ष डॉ. के.सी. चक्रवर्ती द्वारा एक पायलट अध्ययन के बाद सामने आया था। मंगलम गाँव भारत का पहला गाँव बना जहाँ सभी घरों को बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान की गईं। वाणिज्यिक बैंकों ने हिमाचल प्रदेश, केरल और पांडिचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में 100 प्रतिशत वित्तीय समावेशन अभियान शुरू किया और अपने-अपने जिलों में 100 प्रतिशत समावेशन की घोषणा की (आदित्य शास्त्री 2014)। प्राथमिक डेटा उत्तरदाताओं से एक संरचित प्रश्नावली के माध्यम से एकत्र किया जाता है। सर्वेक्षण दिसंबर 2018 से जुलाई 2019 के बीच आयोजित किया गया था। बैंगलोर ग्रामीण जिले के सभी चार तालुकों से पीएमजेडीवाई खाता रखने वाले उत्तरदाताओं से कुल 782 प्रतिक्रियाएँ एकत्र की गईं और केवल 704 प्रतिक्रियाएँ अध्ययन के लिए उपयुक्त थीं और शेष 78 प्रतिक्रियाएँ अधूरी जानकारी के कारण अमान्य थीं। उत्तरदाताओं ने डेटा प्रस्तुत करने में बहुत सहयोग किया। संरचित प्रश्नावली इस तरह से बनाई जाती है कि अध्ययन के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता मिले और उत्तरदाताओं के लिए अपनी प्रतिक्रिया देना आसान और सुविधाजनक हो। संरचित प्रश्नावली विश्लेषण और व्याख्या को आसान बनाती है और उचित निष्कर्ष निकालने में मदद करती है।

डेटा विश्लेषण

डेटा विश्लेषण एकत्रित डेटा का सावधानीपूर्वक निरीक्षण है, ताकि जांच के तहत घटना की विशेषताओं की समीक्षा की जा सके और

शोध से संबंधित चर के बीच संबंधों के पैटर्न का निर्णय लिया जा सके। संपूर्ण शोध प्रक्रिया में डेटा को समझना और व्याख्या करना सबसे कुशल कार्य है। पिछले अध्यायों में सैद्धांतिक पृष्ठभूमि और पिछले साहित्य, विभिन्न योजनाओं की रूपरेखा और शोधकर्ता द्वारा किए गए शोध के स्थान की समीक्षा की गई थी। वर्तमान अध्याय का उद्देश्य संरचित प्रश्नावली के माध्यम से एकत्रित डेटा का विश्लेषण और व्याख्या करना है। वर्तमान अध्याय में, एकत्र किए गए डेटा का विश्लेषण सांख्यिकीय उपकरणों जैसे SPSS संस्करण 25 और AMOS संस्करण 22 का उपयोग करके किया जाता है। उपयोग की जाने वाली सांख्यिकीय तकनीकें एनोवा विद शेफ पोस्ट हॉक, स्वतंत्र टी टेस्ट, एसईएम और मध्यस्थता विश्लेषण हैं।

उत्तरदाताओं का जनसांख्यिकीय प्रोफ़ाइल

जनसांख्यिकीय प्रोफ़ाइल उत्तरदाताओं के संक्षिप्त अवलोकन को संदर्भित करता है और गुणात्मक विश्लेषण में इसे महत्वपूर्ण माना जाता है। उत्तरदाताओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और वित्तीय योजनाओं के बारे में जागरूकता जैसी व्यक्तिगत विशेषताओं पर चर्चा की जाती है।

तालिका 1: उत्तरदाताओं का लिंग दर्शाना

लिंग	उत्तरदाताओं की संख्या	को PERCENTAGE
पुरुष	508	72.2
महिला	196	27.8
कुल	704	100

स्रोत: सर्वेक्षण डेटा

ग्लोबल फ़ाइंडेक्स डेटाबेस (2017) के अनुसार, वैश्विक स्तर पर 65% महिलाओं के पास बैंक खाते हैं। भारत में, हालांकि वित्तीय समावेशन में लैंगिक अंतर 2014 से कम हुआ है, लेकिन तालिका संख्या 1 में वर्तमान अध्ययन ने उन उत्तरदाताओं का प्रतिशत दिखाया है जिन्होंने पीएमजेडीवाई खाता खोला है। डेटा से पता चला है कि महिला उत्तरदाताओं की संख्या 28% है जबकि पुरुष उत्तरदाताओं की संख्या 72% है। यह भी देखा गया है कि ग्रामीण महिलाओं द्वारा बैंक खाता खोलने से न केवल उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार होता है, बल्कि उनके परिवार और समुदाय की समग्र भलाई को बढ़ाने में भी मदद मिलती है।

तालिका 2: उत्तरदाताओं द्वारा योजना के बारे में जागरूकता का स्रोत दर्शाना

योजनाओं के बारे में जागरूकता का स्रोत	उत्तरदाताओं की संख्या	को Percentage
रिश्तेदार	148	21
दोस्त	200	28.4
प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया	222	31.5
बैंक पत्राचार	100	14.2
अन्य	34	4.8
कुल	704	100

स्रोत: सर्वेक्षण डेटा

तालिका संख्या 2 सरकार और आरबीआई द्वारा दी गई योजना के बारे में जागरूकता के स्रोत को दर्शाती है। यह पता चला है कि लिंग ने खाताधारकों की जागरूकता को प्रभावित किया, लेकिन विभिन्न बुनियादी वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के बारे में लाभार्थियों की सामान्य जागरूकता का स्तर कम पाया गया, जिसके लिए कार्यक्रम के पूर्ण लाभों को समझने में उचित भागीदारी की आवश्यकता है (मनोरंजन भुयान एट अल)। जब वित्तीय समावेशन योजनाओं के बारे में जागरूकता के स्रोतों के बारे में पूछा गया, तो 31.5% उत्तरदाताओं में से अधिकांश ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से योजना के बारे में जानकारी प्राप्त की; मित्र और रिश्तेदार जागरूकता का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत थे, उसके बाद क्रमशः बैंक पत्राचार और अन्य थे।

पीएमजेडीवाई योजना के बारे में जागरूकता के स्तर पर लिंग का प्रभाव

लिंग के तीन वर्गीकरण जैसे पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर तथा पीएमजेडीवाई योजना के बारे में जागरूकता के स्तर के कारकों पर उनके सतत अंतर को निम्नलिखित एकतरफा एनोवा तालिका में वर्णित किया गया है। निम्न तालिका पीएमजेडीवाई योजना के बारे में जागरूकता के स्तर पर लिंग के प्रभाव को दर्शाती है।

तालिका 3: पीएमजेडीवाई योजना के बारे में जागरूकता के स्तर पर एनोवा का लिंग प्रभाव

एनोवा					
जागरूकता स्तर		वर्गों का योग	वर्ग मतलब	एफ	सिग.
पीएमजेडीवाई	समूहों के बीच	2.687	1.344	1.323	0.268
	समूहों के भीतर	301.633	1.016		
	कुल	304.32			
डेबिट कार्ड	समूहों के बीच	10.264	5.132	3.155	0.044
	समूहों के भीतर	483.132	1.627		
	कुल	493.397			
क्रेडिट कार्ड	समूहों के बीच	7.504	3.752	1.568	0.21
	समूहों के भीतर	710.496	2.392		
	कुल	718			
औपचारिक और अनौपचारिक ऋण	समूहों के बीच	14.737	7.368	4.033	0.019
	समूहों के भीतर	542.65	1.827		
	कुल	557.387			
बैंकिंग सेवा	समूहों के बीच	14.225	7.113	4.507	0.012
	समूहों के भीतर	468.655	1.578		
	कुल	482.88			
उधार की सुविधाएं	समूहों के बीच	5.761	2.88	1.088	0.338
	समूहों के भीतर	786.436	2.648		
	कुल	792.197			
बीमा सेवा	समूहों के बीच	3.314	1.657	1.26	0.285
	समूहों के भीतर	390.483	1.315		
	कुल	393.797			
पूर्वसेवार्थ वृत्ति योजना	समूहों के बीच	9.66	4.83	4.01	0.019
	समूहों के भीतर	357.727	1.204		
	कुल	367.387			
वित्तीय समावेशन स्रोत: प्राथमिक डेटा से गणना की गई	समूहों के बीच	10.566	5.283	3.602	0.028
	समूहों के भीतर	435.58	1.467		
		446.147			

5% महत्व स्तर पर F का सारणीबद्ध मान 1.880 है। डेबिट कार्ड (3.155), औपचारिक अनौपचारिक ऋण (4.033), बैंकिंग सेवा (4.507), पेंशन योजना (4.01) और वित्तीय समावेशन सेवाओं (3.602) के लिए F का परिकलित मान सारणीबद्ध मान से अधिक है और इसलिए नमूने के औसत मानों में अंतर है।

आगे के विश्लेषण में पाया गया कि अध्ययन क्षेत्र में ट्रांसजेंडर (औसत = 5.00) पीएमजेडीवाई योजना का उपयोग पुरुष और महिला की तुलना में अधिक करते हैं। इसी तरह, ट्रांसजेंडर श्रेणी (औसत = 4.43), (औसत = 4.86) और (औसत = 5.00) बैंकिंग सेवाओं, पेंशन योजनाओं और वित्तीय समावेशन के लाभों का अधिक उपयोग कर रहे हैं। औपचारिक ऋण के मामले में (औसत = 5.00) पुरुष श्रेणी अन्य लोगों की तुलना में अधिक हावी है।

पीएमजेडीवाई योजना के बारे में जागरूकता के स्तर पर व्यवसाय का प्रभाव

खेतीहर, कृषि मजदूर, निर्माण मजदूर, व्यापार वाणिज्य, वेतनभोगी लोग, पेशेवर/स्वयं सेवा और निजी कर्मचारी जैसे व्यवसायों की सात श्रेणियों और पीएमजेडीवाई योजना के बारे में जागरूकता के स्तर के कारकों पर उनके सतत अंतर को निम्नलिखित एकतरफा एनोवा तालिका में वर्णित किया गया है। पीएमजेडीवाई योजना के बारे में जागरूकता के स्तर पर व्यवसाय के प्रभाव को दर्शाती निम्न तालिका।

तालिका 4: पीएमजेडीवाई योजना के बारे में जागरूकता के स्तर पर एनोवा का व्यावसायिक प्रभाव

एनोवा					
जागरूकता स्तर		**वर्गों का योग**	**वर्ग मतलब**	**एफ**	**सिग.**
पीएमजेडीवाई	समूहों के बीच	1.138	0.19	0.183	0.981
	समूहों के भीतर	303.182	1.035		
	कुल	304.32			
डेबिट कार्ड	समूहों के बीच	3.091	0.515	0.308	0.933
	समूहों के भीतर	490.305	1.673		
	कुल	493.397			
	समूहों के भीतर	709.21	2.421		
	कुल	718			
औपचारिक अनौपचारिक ऋण	समूहों के बीच	48.905	8.151	4.697	0.000
	समूहों के भीतर	508.482	1.735		
	कुल	557.387			
बैंकिंग सेवा	समूहों के बीच	27.484	4.581	2.947	0.008
	समूहों के भीतर	455.396	1.554		
	कुल	482.88			
उधार की सुविधाएं	समूहों के बीच	12.507	2.085	0.783	0.584
	समूहों के भीतर	779.689	2.661		
	कुल	792.197			
बीमा सेवा	समूहों के बीच	13.82	2.303	1.776	0.104
	समूहों के भीतर	379.977	1.297		
	कुल	393.797			
पूर्वसेवार्थ वृत्ति योजना	समूहों के बीच	5.716	0.953	0.772	0.593
	समूहों के भीतर	361.671	1.234		
	कुल	367.387			
वित्तीय समावेशन	समूहों के बीच	25.462	4.244	2.956	0.008
	समूहों के भीतर	420.685	1.436		
	कुल	446.147			

स्रोत: प्राथमिक डेटा से गणना की गई

5% महत्व स्तर पर F का सारणीबद्ध मान 1.880 है। औपचारिक और अनौपचारिक ऋण (4.497), बैंकिंग सेवाएं (2.947) और वित्तीय समावेशन (2.956) के लिए F के परिकलित मान सारणीबद्ध मान से अधिक हैं और इसलिए नमूने के औसत मानों में कोई अंतर नहीं है।

आगे के विश्लेषण में पाया गया कि निर्माण श्रमिक (औसत = 2.98) अन्य व्यवसाय समूह की तुलना में पीएमजेडीवाई योजना के बारे में अधिक जागरूक हैं। (औसत = 4.07) व्यापार वाणिज्य समूह बैंकिंग सेवाओं का अधिक उपयोग करते हैं और वेतनभोगी लोग (औसत = 4.21) अन्य लोगों के समूह की तुलना में अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक अधिक पहुंच रखते हैं।

पीएमजेडीवाई योजना के बारे में जागरूकता के स्तर पर मासिक आय का प्रभाव

मासिक आय के चार वर्गीकरण 2000 - 5000, 5000 -10000, 10000 - 15000 और 15000 से अधिक तथा पीएमजेडीवाई योजना के बारे में जागरूकता स्तर के कारकों पर उनके सतत अंतर को निम्नलिखित एकतरफा एनोवा तालिका में दर्शाया गया है। निम्न तालिका पीएमजेडीवाई योजना के बारे में जागरूकता स्तर पर मासिक आय आयु के प्रभाव को स्पष्ट करती है।

निष्कर्ष

देश की आर्थिक वृद्धि दर गरीबी उन्मूलन के लिए बैरोमीटर का काम करती है। "2019 वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक" रिपोर्ट के अनुसार, भारत की 27.9% (369 मिलियन) आबादी बहुआयामी गरीबी में रहती है। भारत सरकार द्वारा 2020 तक भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए ठोस प्रयास किए गए हैं और इस मिशन को प्राप्त करने के लिए सरकार विभिन्न वित्तीय समावेशन कार्यक्रम शुरू कर रही है। राष्ट्र का समग्र विकास तभी माना जाता है जब समाज के वंचित वर्ग को औपचारिक रूप से वित्तीय प्रणाली से परिचित कराया जाता है। वर्तमान अध्ययन बैंगलोर ग्रामीण जिले में ग्रामीण गरीबों के बीच प्रधानमंत्री जन धन योजना के प्रभाव को उजागर करने और यह आकलन करने के लिए किया गया है कि क्या योजना ने अपने उद्देश्य को पूरा किया है। पीएमजेडीवाई द्वारा निर्देशित हस्तक्षेपों के छह साल के मार्ग ने परिवर्तनकारी और दिशात्मक बदलाव लाए हैं, जिससे वित्तीय समावेशन पारिस्थितिकी तंत्र को बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की अनुमति मिली है, जो कि सबसे निचले तबके के लोगों को भी मिल रही है। लोगों पर केंद्रित आर्थिक परियोजनाओं की जड़ें पीएमजेडीवाई में हैं। उनका बैंक खाता खोलना आवश्यक था, जो कि पीएमजेडीवाई योजना के तहत व्यावहारिक रूप से पूरा हो चुका है, ताकि सरकार की कई जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समुदाय के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाया जा सके।

संदर्भ

1. चरण सिंह, आकांक्षा मित्तल, अक्षय सिंह, सिरिगनी राहुल, कार्तिक, वैभव, रवि, रितेश, उज्ज्वल "भारत में वित्तीय समावेशन-चुनिंदा मुद्दे", भारतीय प्रबंधन संस्थान बैंगलोर, कार्य पत्र संख्या, 2014, 474, पृष्ठ 1-43।
2. गर्ग सोनू, अग्रवाल पारुल, भारत में वित्तीय समावेशन- पहल और उपलब्धियों की समीक्षा, आईओएसआर जर्नल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट, खंड. 2014;16(6):52-61.
3. जॉन डी. विलासेनोर, डेरेल एम. वेस्ट, और रॉबिन जे. लुईस, "वित्तीय और डिजिटल समावेशन: डिजिटल पहुंच और उपयोग पर प्रगति को मापना", द ब्रुकिंग रिपोर्ट, 2015.
4. वैश्विक वित्तीय विकास रिपोर्ट, वित्तीय समावेशन 2014।
5. डॉ. इप्सीतासत्पथी, डॉ. बीसीएमपटनायक और सुश्री मीतू अग्रवाल, अर्ध-शहरी क्षेत्र में मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के बारे में जागरूकता पर एक आत्मनिरीक्षण" इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट (आईजेएम), खंड 5, अंक 9, 2014, पृष्ठ

13 - 17, आईएसएसएन प्रिंट: 0976-6502, आईएसएसएन ऑनलाइन: 0976-6510।
6. कुंथिया आर; "प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई): भारत में वित्तीय समावेशन की दिशा में एक नया अभियान", जेनिथ इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट रिसर्च, खंड 4, संख्या 11, नवंबर 2014; पृष्ठ -10
7. सुमति एम; "वित्तीय समावेशन एक अवलोकन", द इकोनॉमिक चैलेंजर, अंक 58, संख्या 15, जनवरी-मार्च 2013; पृ- 68
8. भुवनेश्वरी पी और पुष्पलता वी; "वित्तीय समावेशन के साधन के रूप में सामाजिक बैंकिंग", आपके लिए व्यवसाय और आर्थिक तथ्य, खंड 33, संख्या 8, मई 2013; पृष्ठ - 30
9. डांग एन और कुमार पी; "भारत में वित्तीय समावेशन की वर्तमान स्थिति और इसके भविष्य के दृष्टिकोण", इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट एंड सोशल साइंसेज रिसर्च, खंड 2, संख्या 8, अगस्त 2013; पृष्ठ- 155
10. सिन्हा ए; "वित्तीय समावेशन और शहरी सहकारी बैंक", भारत में आर्थिक विकास, खंड 171, 2013; पृष्ठ - 59.
11. सोनम कुमारी गुप्ता. प्रधानमंत्री जन धन योजना का प्रदर्शन मूल्यांकन, आईओएसआर जर्नल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट (आईओएसआर-जेबीएम), खंड, 2015, 17(9). संस्करण ।, पृष्ठ 35-39।
12. हरप्रीत कौर और कवल नैन सिंह. "प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई): भारत में वित्तीय समावेशन की दिशा में एक छलांग", इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इमर्जिंग रिसर्च इन मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, खंड, 2015, 4(1), पृष्ठ 25-29।
13. दिव्येश कुमार. प्रधानमंत्री जन-धन योजना का उपयोग करके वित्तीय समावेशन - एक संकल्पनात्मक अध्ययन", एशिया पैसिफिक जर्नल ऑफ रिसर्च आईएसएसएन: 23205504, ई-आईएसएसएन-2347-4793, खंड, 2014, 1(20), पृष्ठ.37-42
14. बरहाटे जीएच और जगताप वीआर, प्रधानमंत्री जन-धन योजना: वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एप्लाइड रिसर्च, खंड 4, संख्या 12, दिसंबर 2014, पृ. 340-342. चौहान
15. सेनापति. ओडिशा में प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) योजना और वित्तीय समावेशन की चुनौतियों का एक अध्ययन।, 2018.

Creative Commons (CC) License
This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.